कल्याणकार्य करने वाला एक संगठन) के लिए कुछ उन फर्मों, जिनसे उनके सरकारी पद पर होने से संबंध थे, से दान एकत्र करने में उचित विवेक की कमी दिखाई थी। दान की यह राशि केवल 350/- रुपये थी। नियंत्रक को तद्नुसार यह लिखित चेतावनी दे दी गई थी कि "भविष्य में वे अधिक सतर्कता से काम करें।"

3. नियंत्रक के विरुद्ध दूसरा जो आरोप सिद्ध नहीं हो सका वह यह था कि मार्च-अप्रैल 1977 में जिस समय वे अस्पताल में इलाज करवाने के लिए भर्ती थे उस समय परिवार के सदस्यों ने पूना और अहमदनगर के बीच परीक्षण के लिए जाने वाली कारों में कभी-कभी लिफ्ट ली थी। यद्यपि इससे सरकार को कोई अतिरिक्त व्यय नहीं करना पड़ा फिर भी इसे सरकारी अधिकारों का उल्लंघन माना गया और उक्त अफसर को भविष्य में ऐसी लापरवाही न करने की चेतावनी दी गई।

4. जहां तक अपने निजी प्रयोग के लिए कार प्राप्त करने का प्रश्न है, यह पाया गया कि नियंत्रक ने कार सीधे कार निर्माता मेसर्स हिन्दुस्तान मोटर्स कलकत्ता से खरीदी थी। किन्तु उक्त कार फर्म के ड्राइवर द्वारा कलकत्ता से अहमदनगर लाई गई थी, यद्यपि उस का खर्च उक्त अफसर ने वहन किया था। इस संबंध में भी उक्त नियंत्रक को एक मौखिक चेतावनी दी गई थी।

5. नियंत्रक का अहमदनगर से स्थानान्तरण भी कर दिया गया था किन्तु उन्होंने सेवा से त्याग-पत्र दे दिया और वे सितम्बर 1979 में सेवा से समय-पूर्व ही सेवा-निवृत्त हो गए।

रक्षा मंत्रालय में हिन्दी का प्रयोग

7010. **श्री धर्मदास शास्त्री:** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि मंत्रालय विशेषकर जनसम्पर्क निदेशालय में हिन्दी भाषा की अपेक्षा की जाती है और हिन्दी समाचार-पत्रों की कतरनें भी तैयार नहीं की जाती जबकि क्षेत्रीय अंग्रेजी समाचार-पत्रों की कतरनें प्रतिदिन तैयार की जाती है;

(ख) क्या यह भी सच है कि नौसैनिक जहाजों के साथ उनकी अन्य देशों की सद्भावना यात्राओं के समय कुछ संवाददाता भी जाते हैं परन्तु उनमें हिन्दी संवाददाताओं को कभी भी सम्मिलित नहीं किया गया;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है;

(घ) क्या यह भी सच है कि जन-सम्पर्क अधिकारी (हिन्दी) का पद काफी समय से खाली पड़ा है; और

(ङ) यदि हां, तो इस पद को अब तक न भरे जाने के क्या कारण है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी. पी. एन. सिंह): (क) यह सच नहीं है कि रक्षा मंत्रालय अथवा जन-सम्पर्क निदेशालय जो इसका अधीनस्थ कार्यालय है, में हिन्दी की उपेक्षा की जा रही है। इस निदेशालय में हिन्दी के समाचार-पत्रों की कतरनें पत्र सूचना कार्यालय से आती हैं। चूंकि अंग्रेजी समाचार-पत्रों की कतरनें पत्र सूचना कार्यालय द्वारा उपलब्ध नहीं करवाई जाती हैं अत. ये जन-सम्पर्क निदेशालय में ही तैयार की जाती हैं।

(ख) और (ग). नौसेना के एक या दो जहाज हर वर्ष दूसरे देशों की सद्भावना यात्राये करते हैं। ऐसे जहाजों में जगह उपलब्ध होने की स्थिति में प्रत्येक जहाज के साथ एक या दो संवाददाता भेजे जाते हैं। जब केवल एक संवाददाता के लिए ही जगह उपलब्ध होती है तो अंग्रेजी समाचार एजेन्सी में एक संवाददाता भेज दिया जाता है। दो संवाददाताओं के लिए जगह उपलब्ध होने पर एक संवाददाता अंग्रेजी समाचार एजेन्सी का तथा दूसरा भारत के समुद्र तटीय क्षेत्र से अंग्रेजी अथवा क्षेत्रीय भाषा के दैनिक पत्र का संवाददाता भेजा जाता है। यह व्यवस्था निम्नलिखित कारणों से सुविधाजनक समझी गई है:--

(1) अंग्रेजी समाचार एजेन्सियों का क्षेत्र व्यापक है और ये हिन्दी के समाचार पत्रों की मांग भी पूरी करती हैं।

(2) अंग्रेजी समाचार से संबंधित पत्र-पत्रिकायें उन समुद्र तटीय क्षेत्रों में उपलब्ध कराई जाती हैं जहां नौ-सेना की

अधिकतर स्थापनाएं हैं और जहां हिन्दी समाचार पत्र बहुत कम हैं।

(3) इससे अंग्रेजी एजेन्सियों/दैनिक पत्रों के संवाददाताओं को विदेशों से समाचार भेजने में कुछ हद तक सहायता मिलती है क्योंकि नौसेना की सिगनल सेवा केवल अंग्रेजी में ही है।

हिन्दी समाचार एजेन्सी अथवा हिन्दी के दैनिक पत्र का कोई संवाददाता भेजने से समाचारों का परिचालन केवल हिन्दी भाषी क्षेत्रों तक ही सीमित रहेगा और इससे समाचारों का प्रसारण केवल हिन्दी भाषी क्षेत्रों में ही हो सकेगा जहां नौसेना की प्रमुख स्थापनाएं नहीं हैं।

(घ) जी नहीं ।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

Proposal to separate Intelligence Bureau from Police

7011. SHRI JYOTIRMOY BOSU : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government are contemplating to separate the Intelligence Bureau from the Police; and

(b) if so, details and reasons thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI YOGENDRA MAKWANA) : (a) The Intelligence Bureau is not a police organisation and as such, the question of separating it from the police does not arise.

(b) Do not arise.

Supply of Enriched Uranium by U.S.A.

7012. SHRI CHITTA BASU:
SHRIMATI PRAMILA DANDAVATE:

Will the PRIME MINISTER be please to state the latest position in regard to the supply of enriched Uranium by U.S.A. for Tarapur Atomic Plant?

THE PRIME MINISTER (SHRIMATI INDIRA GANDHI): On June 19, 1980 the President of the United States authorised the export of both the pending shipments of enriched uranium by an Executive Order which would be subject to review by the U.S. Congress for 60 days of continuous session. This period of Congressional review is expected to conclude by end September 1980. The debate on the subject is continuing in the U.S. Congress.

Deputation of Bengalis in Assam

7013 SHRI K. P. SINGH DEO: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a deputation of Bengalis residing in Assam came to Delhi on the 8th July, 1980 and presented a memorandum to the Prime Minister;

(b) if so, the details of the demands made in the memorandum; and

(c) Government's reaction in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI YOGENDRA MAKWANA): (a) and (b). A memorandum dated 8th July, 1980, addressed to the Prime Minister by Assam Bengali Association, P.O. Sapatgram-783337', District Goalpara (Assam) was received. The memorandum mainly complains of alleged partisan, conduct of Assam Police and demands that Assam Police Battalion should be removed and more Central Forces like CRPF and BSF be stationed for the safety, security and protection of the minorities.

(c) Assam Government had been requested to take all steps to protect the lives and properties of minorities in Assam. The State Government have also issued instructions to the concerned officers to ensure adequate protection to minorities and to firmly deal with any violent activities emphasising quick detection and arrest